



सांध्य दैनिक 4PM



किसी के लिए अपना सब कुछ
कुर्बान कर देना इतना
मुश्किल नहीं है, लेकिन उस
इंसान को खोज पाना मुश्किल
है जो आपके कुर्बानी का सम्मान करे।
—ब्रह्माकुमारी शिवानी

मूल्य
₹ 3/-

जिद...सच की



www.4pm.co.in



www.facebook.com/4pmnewsnetwork



@Editor_SanjayS



YouTube



@4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक 249 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 17 अक्टूबर, 2026

न्यूजीलैंड टूर के लिए भारत की टेस्ट... 7 बिहार के बाद मप्र में भी एनडीए... 3 आज 'एकरंगा' बनाम 'तिरंगा' का... 2

तिरंगे से डरती सत्ता, दुनिया तक पहुंचता जंतर-मंतर का शोर

राहुल के वोट वाले सवाल से मार्को रूबियो की मेज तक पहुंचा लोकतंत्र का मुद्दा

अमेरिकी
सांसदों
की चिट्ठी
ने बढ़ाई
दिल्ली
की
बेचैनी

तिरंगा हाथ में हो तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है

कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के प्रकरण ने इस बहस को प्रतीकात्मक ताकत दी है। सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस बैरिकेड पार कर प्रदर्शन करने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद दीपके ने दोबारा प्रदर्शन

का आह्वान किया और 16 अक्टूबर को उन्हें भी हिरासत में लिया गया फिर औपचारिक गिरफ्तारी की खबर सामने आई। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय पाठकों के सामने रखा। उसकी रिपोर्ट के अनुसार दीपके तिरंगा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था और शांति भंग होने की आशंका जैसे कारण सामने आए हैं।



» दीपके की गिरफ्तारी और सौरव दास-आशुतोष रांका की जेल ने खड़े किए तीखे सवाल

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में बैरिकेड खड़े किए गए रास्तों पर पहरे बिठाए गए प्रदर्शन की जगह को लेकर पाबंदियां लगाई गईं और विरोध की आवाज उठाने वालों को हिरासत में लिया गया। सत्ता शायद सोच रही थी कि राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा छा जाएगा तो सवाल भी दम तोड़ देंगे। लेकिन राजनीति में कई बार जिस आवाज को दबाने की कोशिश होती है वही आवाज दीवारों के पार निकल जाती है।

जंतर-मंतर के विरोध की गूंज अब अमेरिकी सांसदों के पत्र और संयुक्त राष्ट्र की शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार संबंधी अपील के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गये हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को छह सांसदों ने पत्र लिखकर भारत यात्रा के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी मानवाधिकार और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दे उठाने को कहा है। दूसरी ओर भारत सरकार

दिल्ली का सन्नाटा वाशिंगटन की चिट्ठी और लोकतंत्र की परीक्षा

जंतर मंतर की कहानी अब दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा से पहले छह अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर भारतीय अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शनों मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उठाने का आग्रह किया है। पत्र लिखने वालों में



6

अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर अभिव्यक्ति की आजादी मानवाधिकार और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दे उठाने को कहा है।

प्रमिला जयपाल, इल्हान उमर, जिम मैकगवर्न, रशीदा तलैब, एलिनॉर होम्स नॉर्टन और जीसस गार्सिया शामिल हैं। सांसदों ने अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशनों से जुड़े लोगों द्वारा प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लेने और निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। इन पत्रों के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि भारतीय विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा अब अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है।

आलोचना से भागिए मत जवाब दीजिए सरकार

भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा केवल इस बात से नहीं बनती कि यहां चुनाव होते हैं। उसकी असली ताकत इस बात में है कि चुनाव पर सवाल उठाने वाले को जवाब मिलता है या सत्ता सेक दिया जाता है। असह्यति रखने वाले को तर्क सुनने को मिलता है या हिरासत का डर। और नागरिक को शिकायत

करने का अधिकार मिलता है या चुप रहने की सलाह। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किसी एक चिट्ठी से न बनती है न बिगड़ती है। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार चर्चा में रहें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल जल्द उठते हैं। अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी को भारत की ओर से खारिज किया

जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी पर सरकार आपत्ति जता सकती है। मगर इन प्रतिक्रियाओं से जंतर-मंतर के सवाल समाप्त नहीं होंगे। उनका जवाब भारतीय नागरिकों को चाहिए चुनाव आयोग की पारदर्शिता से पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही से और विरोध के अधिकार की स्पष्ट सुरक्षा से।

राहुल गांधी के सवाल और मतदाता सूची का महाविवाद

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विवाद भी है। राहुल गांधी और विपक्ष चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटने से वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग के

आंकड़ों के अनुसार पुनरीक्षण प्रक्रिया में करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए जिनमें मृत और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसलिए नाम हटने की कुल संख्या अपने आप में यह साबित नहीं करती कि सभी नाम गलत तरीके से हटाए गए। असली प्रश्न यह है कि कितने वास्तविक मतदाता प्रभावित हुए उन्हें सूचना मिली या नहीं और सुधार की प्रक्रिया कितनी सुलभ रही।

और विदेशी सांसदों की चिट्ठी ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। सत्ता के

लिए असली चुनौती आलोचना को रोकना नहीं बल्कि आलोचना के बीच

अपने लोकतांत्रिक दावों पर भरोसा कायम रखना होता है।

आज 'एकरंगा' बनाम 'तिरंगा' का दिन: अखिलेश

» सपा प्रमुख ने भाजपा पर साधा निशाना

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तिरंगा मार्च को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। यूपी पर्व सीएम ने भाजपा पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि आज 'एकरंगा' बनाम 'तिरंगा' का दिन है! बता दें दिल्ली के कनॉट प्लेस में काँकरोच जनता पार्टी के तिरंगा मार्च से पहले संस्थापक अभिजीत दिपके और आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया गया।

यह प्रदर्शन मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर था। तनाव को देखते हुए सेंट्रल पार्क के पास धारा 144 लगाकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लहरा दो तिरंगा विरोध प्रदर्शन ने एक नया मोड़ ले लिया है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित मार्च से पहले, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा को एहतियातन वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि विपक्ष द्वारा सत्ता परिवर्तन% जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके उस एजेंडे को साफ कर देता है, जिसके तहत वे विदेशी ताकतों के साथ मिलकर



वन करप्शन, वन इलेक्शन लागू करना चाहती है भाजपा

अखिलेश यादव ने कहा कि वन नेशन वन-इलेक्शन, भाजपा का वन करप्शन (भ्रष्टाचार), वन इलेक्शन है। भाजपा चाहती कि एक बार बेईमानी, भ्रष्टाचार और वोटों की लूट कर चुनाव हो जाए जिससे बार-बार घपला न करना पड़े। इनके वन नेशन-वन इलेक्शन के षडयंत्र को जनता समझ गयी है। उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएससी जैसी कंपनी भी मतदाता सूची के घपले में भाजपा के साथ शामिल है।

देश को अस्थिर करना चाहते हैं। नबीन ने एक पोस्ट में कहा सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने देश के सामने विपक्ष के असली एजेंडे को उजागर कर दिया है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की यह नापाक कोशिश, अर्बन नक्सलियों के एजेंडे का ही हिस्सा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है।

एक तरफ मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिरंगा लिए प्रदर्शनकारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जवानों ने इलाके को घेर लिया है, जबकि तिरंगा लिए लोग सेंट्रल पार्क के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं (सेंट्रल पार्क अभी आम लोगों के लिए बंद है)। संसद मार्ग और जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्ते

पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जहाँ अर्धसैनिक बलों के जवान और महिला कांस्टेबल तैनात हैं। यहाँ धारा 144 लागू होने का बोर्ड भी लगा है। हालाँकि, बैरिकेड के बगल वाली सड़क खुली है, जहाँ कनॉट प्लेस के इनर सर्कल से ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच, पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।

भाजपा की साजिश पीडीए प्रहरी विफल करेंगे

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके गैरपंजीकृत दरारवादी लोग जानते हैं कि अब वे चुनाव में सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मतदाता सूची का एसआईआर हो चुका है, लेकिन अब फिर से एसएसआर कराया जा रहा है। इस एसएसआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) का उल्टा आरएसएस है, भाजपा अपने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नए-नए षडयंत्र और साजिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के पीडीए प्रहरी मिलकर इन साजिशों को विफल करेंगे। सपा के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की कि 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को अपने-अपने बूथों पर रहें। अपना वोट जुड़ाएँ। फर्जी वोट बनने से रोके। मतदाता सूची पर निगरानी रखें। अखिलेश ने चुनाव आयोग से कहा कि एक वोटर लिस्ट का एक ही रिवीजन करें, रिवीजन के ऊपर रिवीजन न करें। यह तय होना चाहिए कि एसएसआर के बाद अब मतदाता सूची का कोई रिवीजन न हो। जब एसएसआर का फैसला ले लिया है तो अब वही आखिरी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी डबल रिवीजन के पक्ष में नहीं है।

वाराणसी लोस सीट प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए जीती बीजेपी: अजय राय

» कांग्रेस नेता और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीएम मोदी पर भड़के

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वाराणसी। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट कथित चुनावी धांधली और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए जीती है। साथ ही, उन्होंने 2024 के आम चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

राय की यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी (सपा) के समर्थन के बिना चुनाव जीतने की चुनौती दी थी। सिंह की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राय ने कहा कि रक्षा मंत्री को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सवालों का भी जवाब देना चाहिए, जहां से पीएम मोदी 2024 में लगातार तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे समाजवादी पार्टी के बिना कोई चुनाव जीतकर दिखाएँ; शायद उन्हें असल तथ्यों की जानकारी



नहीं है। राय ने कहा, रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से हमारी नेता सोनिया गांधी 2019 से 2024 तक सांसद रहीं, और उसके बाद राहुल गांधी भी उसी सीट से सांसद रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस की मौजूदगी का हवाला देते हुए, राय ने राहुल गांधी के गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर होने संबंधी राजनाथ सिंह के बयान पर सवाल उठाया और चर्चा का रुख वाराणसी में प्रधानमंत्री की चुनावी जीत की ओर मोड़ दिया। राय ने आरोप लगाया मैं राजनाथ सिंह से बनारस सीट के बारे में पूछना चाहूंगा। एक ऐसे सीट जिसे पीएम मोदी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के सहारे, चोरी और धांधली के जरिए जीता है। कांग्रेस नेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया

कि शुरुआती राउंड में पीएम मोदी पीछे चल रहे थे, और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से मिलने वाले अपडेट दोपहर के आसपास रुक गए थे, जिसके बाद सीधे शाम को अंतिम परिणाम घोषित किए गए। राय ने कहा प्रधानमंत्री सात राउंड तक पीछे चल रहे थे, फिर भी चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे के बाद चुनाव के अपडेट देना बंद कर दिया, और शाम 7 बजे यह घोषित कर दिया कि वे जीत गए हैं।

पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर किस तरह के चमत्कार से प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की जीत में उनके सहयोगी दलों के समर्थन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की भूमिका रही। साथ ही, उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा पूरी प्रक्रिया को संभालने के तरीके पर भी सवाल उठाए। राय ने सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह को भी निशाने पर लिया और कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाने से पहले, उन्हें वाराणसी के नतीजों से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। राय ने अपनी पोस्ट में लिखा, क्या प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है कि वे सहयोगी दलों के समर्थन और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के बिना, अकेले चुनाव लड़ सकें?

यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे आकाश आनंद, मायावती ने दी फिर जिम्मेदारी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर स. आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद और पार्टी अध्यक्ष मायावती का आशीर्वाद मिलने के बाद आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ताकि, आगामी चुनावों में पार्टी के सियासी जनाधार को फिर से जोड़कर और मजबूत किया जा सके।

बसपा में वापसी के बाद आकाश आनंद पर मायावती ने भरोसा जताते हुए उन्हें यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी है। अगले दो महीनों में इन राज्यों में आकाश आनंद की सात बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से आकाश आनंद का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अलावा कई विधानसभा के बसपा नेता भी उनकी रैली कराए जाने की माँग कर रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले आकाश आनंद की प्रदेश में सक्रियता बढ़ने जा रही है। आकाश आनंद 28 अक्टूबर को बुलंदशहर के अनूपशहर से चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। अनूपशहर में बसपा की ओर से एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर



को सहारनपुर के नकुड़, 20 नवंबर को अयोध्या के बीकापुर, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर के बिल्हौर में आकाश आनंद की जनसभा कराए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड में भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इन रैलियों के जरिए बसपा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेगी। आकाश आनंद 26 नवंबर को पंजाब और 6 दिसंबर को हरिद्वार में भी सभा करेंगे। आकाश आनंद का बसपा समर्थक युवाओं के बीच उनका खासा क्रेज देखने को मिलता है। उनका आक्रामक अंदाज़ उन्हें पसंद आता है। बता दें कि आकाश आनंद कई बार बहुजन समाज पार्टी से कभी बाहर तो कभी अंदर होते रहे हैं। मायावती ने दिसंबर 2023 में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था।



शिवसेना यूबीटी छोड़ आनंद दुबे शिंदे गुट में पहुंचे

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) से इस्तीफा देने वाले आनंद दुबे, ठाणे में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में, आनंद दुबे ने इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

कई सालों तक, वे पार्टी के एक मुखर रक्षक रहे, जिन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पार्टी की नीतियों का बचाव किया। लेकिन अब यह बचाव खत्म हो गया है। भारी मन और दृढ़ स्वर में, उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ने की घोषणा की। मैं अपनी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी) से इस्तीफा दे रहा



हूँ। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद, दोनों से पूरी तरह से अलग हो रहा हूँ। उनका इस्तीफा पार्टी के कामकाज को लेकर चल रही नाराजगी के बीच आया है। उनके पार्टी छोड़ने से शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी मतदाताओं तक पहुंचने के मामले में। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब महा विकास अघाड़ी (- जिसमें

शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं - अपने घटकों के बीच एकता पर जोर दे रही है। अपने इस फैसले की गंभीरता को समझाते हुए, दुबे ने बताया कि यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहे आंतरिक संघर्ष का नतीजा था। कई सालों तक, उन्होंने बदलते राजनीतिक समीकरणों का बोझ चुपचाप ढोया था। पिछले चार-पांच सालों से, मैंने महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों से लेकर ग्रीष्म और अंतरराष्ट्रीय मामलों तक, हर विषय पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा है। तो फिर, क्या बदल गया? कुछ भी रातों-रात नहीं होता। कई महीनों से, मैं चुपचाप तकलीफ सह रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था।

बिहार के बाद मप्र में भी एनडीए में रार !

सम्राट पर चिराग की आग, जदयू में नेताओं में सिर फुटव्वल, सम्राट पर चिराग की आग, जदयू में नेताओं में सिर फुटव्वल

- » मीटिंग में भी शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ऐसे दिखे, पार्टी भी है असहज
- » एमपी में आदिवासियों ने रुढ़ किया अपना भोपाल मार्च
- » सीएम मोहन यादव ने दिया है न्याय का भरोसा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

भोपाल। आंदोलनों की आग से झुलस रही एनडीए सरकार क्या अपने नेताओं के आपसी विवादों की तपिश भी झेल रही है। ऐसा लगता है कि बिहार में जदयू व लोजपा में मतभेद आने के बाद अब मप्र में अब भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि कोसमी के आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी की दरारें बाहर आ गई हैं। हालांकि देर रात इसका पटाक्षेप हो गया है।

आदिवासी वापस लौट गए हैं लेकिन कई सवाल छोड़ गए हैं। मीटिंग के दौरान दोनों बड़े नेता सहज नहीं दिखे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह असहज करने वाली स्थिति है। सीहोर में आदिवासी परिवारों का घर गिराए जाने का विरोध भोपाल की ओर बढ़ रहा था। इसके जरिए मोहन सरकार पर प्रेशन क्रिएट करने की तैयारी थी लेकिन देर रात इसका पटाक्षेप हो गया है। आदिवासी आधे रास्ते से वापस लौट गए। मगर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति असहज हो गई है।

भोपाल मार्च कर रहे थे आदिवासी : कोसमी गांव में घर तोड़े जाने के बाद वन विकास निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों को कोई हल नहीं मिला था। पांच दिनों बाद आदिवासियों ने भोपाल मार्च का फैसला किया था। कोसमी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता हैं, यहां से शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे हैं। देर रात सीएम हाउस में मीटिंग के बाद आदिवासी वापस लौट गए हैं।

अधिकारियों को लेकर कई शिकायतें : हालांकि अन्य नेता और विधायक भी इस बात की शिकायत मौजूदा सरकार में करते रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। कई मंत्री भी कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। वहीं, सरकार इन चीजों को खारिज करती रही है।



वन विभाग का तर्क

हालांकि इस कार्रवाई को लेकर वन विभाग का कहना था कि यह कार्रवाई वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है। यहां 2021 में पौधा रोपण किया गया था। लेकिन इसके विपरीत पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम वर्षों से यहां रह रहे हैं। साथ ही पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे हैं। साथ ही अपनी जमीन को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं।

बीजेपी को वोट देने वालों को क्यों टारगेट किया जा रहा

इस कार्रवाई को हवा तब मिली जब शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर अपनी सरकार के अधिकारियों फटकार लगाई। साथ ही कहा था कि बीजेपी को वोट देने वाले परिवारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है।

सीएम ने दिया न्याय का भरोसा

गुरुवार देर रात आदिवासी प्रतिनिधियों और सीएम मोहन यादव के साथ मीटिंग हुई है। इसमें उन्होंने भरोसा दिया है कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। सभी को पक्का इंसाफ मिलेगा।

असहज दिखे तीनों नेता

रात में हुई मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खडेलवाल मौजूद थे। तीनों आसपास ही बैठे थे लेकिन बौंदी लैंग्वेज काफी कुछ इशारा कर रहा था।



सम्मान की है लड़ाई

गौरतलब है कि आदिवासियों से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान के लिए यह सम्मान की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में अपनी जमीन को न तो वह खोना चाहते हैं और न ही यहां से दूर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि रह-रहकर वह फूट पड़ते हैं। अब देखते हैं कि दो बड़े नेताओं के बीच चल रहे इस विवाद को पार्टी कैसे हैंडल करती है।

कार्यकर्ताओं की समस्याएं सीधे सुनेंगे पार्टी नेता

भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अपने कार्यकर्ताओं की चिंताओं और शिकायतों को सुनने के लिए दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय मुख्यालय में रोज़ाना जन सुनवाई शुरू की है। यह पहल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में लागू की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद को आसान बनाना है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी तरुण चुध ने इस संपर्क कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की देखरेख की है। सोमवार से शुक्रवार तक, पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान के लिए काम करेंगे। मुख्यालय भवन के मल्टीपर्स हॉल में नियमित रूप से जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिवों, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपलब्धता के लिए दिन-वार रोस्टर जारी



किया है। ये पदाधिकारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अपने निर्धारित कमरों में उपलब्ध रहेंगे, और दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ग्राउंड फ्लोर पर स्थित मल्टीपर्स हॉल में जन सुनवाई के लिए मौजूद रहेंगे।

सोमवार को राष्ट्रीय महासचिव विनोद



तावड़े और हरीश द्विवेदी हर हफ्ते मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष राम माधव और सचिव कविता पाटीदार पहले और तीसरे हफ्ते में मौजूद रहेंगे, जबकि उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और भारती प्रवीण पवार तथा सचिव संदीप पाठक और स्वदेश सिंह दूसरे और चौथे हफ्ते में मौजूद रहेंगे।

मंगलवार को महासचिव सुनील बंसल और गजेंद्र पटेल हर हफ्ते उपलब्ध रहेंगे। संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश, उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और सचिव जगदीश पटेल पहले और तीसरे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल और सचिव संगीता



यादव तथा अनिल एंटनी दूसरे और चौथे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। बुधवार को महासचिव बिप्लव कुमार देब और संजय भाटिया हर हफ्ते मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी और सचिव के. सुरेंद्रन पहले और तीसरे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य और सचिव एम. वैकटेशन तथा मुगांका देव बर्मन दूसरे और चौथे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। गुरुवार को महासचिव स्मृति ईरानी और मुख्यालय प्रभारी तरुण चुध हर हफ्ते मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और सचिव भोला सिंह पहले और तीसरे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। उपाध्यक्ष एम. नागराज और सचिव सिद्धार्थ शंभू तथा रोहन गुप्ता दूसरे और चौथे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को महासचिव सतीश पूनिया हर हफ्ते उपलब्ध रहेंगे। उपाध्यक्ष वर्षाबिन दोषी और मधुचंद्र कर तथा सचिव प्रदीप वर्मा पहले और तीसरे हफ्ते में मौजूद रहेंगे। संयुक्त महासचिव (संगठन) सौदान सिंह, उपाध्यक्ष तीर्थ सिंह रावत और तारिक मंसूर, तथा सचिव फांगनोन कोन्याक, मनोज टिग्गा और जय प्रकाश दूसरे और चौथे हफ्ते में मौजूद रहेंगे।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

अन्न उत्पादन में लगीं महिला किसानों का भी बड़े सम्मान

66

महिलाएं खेतों में श्रम के साथ पशुधन प्रबंधन, बागवानी, मत्स्य पालन, बीज संरक्षण और कृषि उपज के प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी कृषि में सक्रिय भागीदारी हमेशा किसान के रूप में संस्थागत पहचान और संसाधनों पर अधिकार में परिवर्तित नहीं होती। निराई, कटाई, बीज सफाई और प्रसंस्करण जैसे कार्यों में उपयुक्त उपकरण महिलाओं का समय और शारीरिक श्रम बचा सकते हैं।

भारत में अन्न उत्पादन में महिला किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वे खेल से लेकर अन्न को घर आने तक अपनी मेहनत से उसे संवारती हैं। इसलिए देश को उनकी भागीदारी का सम्मान करना चाहिए। बल्कि अन्य कार्यों में उनकी भागीदारी और बढ़ानी चाहिए। प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग, डिजिटल सेवाओं और बाजार संपर्क से कृषि उद्यमिता के नए अवसर बन रहे हैं। महिला उद्यमियों की भागीदारी परिवर्तन को नई दिशा दे रही है। भारत के खेतों में अंकुरित होने वाला हर बीज केवल अन्न का वादा नहीं, बल्कि किसी महिला किसान के श्रम, अनुभव और प्रकृति के साथ पीढ़ियों के संवाद का परिणाम भी है। बुवाई से कटाई, पशुपालन से बीज संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण से परिवार की पोषण सुरक्षा तक महिलाओं की भूमिका भारतीय कृषि की आधारशिला है। आज जरूरत इस भूमिका को कृषि संसाधनों, आधुनिक तकनीक, बाजार और निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी तथा नेतृत्व के अवसरों से सशक्त बनाने की है। 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस महिलाओं के कृषि योगदान को रेखांकित करने और उनकी क्षमता को नए अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। महिलाएं खेतों में श्रम के साथ पशुधन प्रबंधन, बागवानी, मत्स्य पालन, बीज संरक्षण और कृषि उपज के प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी कृषि में सक्रिय भागीदारी हमेशा किसान के रूप में संस्थागत पहचान और संसाधनों पर अधिकार में परिवर्तित नहीं होती। कृषि जनगणना 2015-16 में परिचालित जेतों में महिला परिचालकों की हिस्सेदारी लगभग 14 प्रतिशत दर्ज की गई थी। भूमि, ऋण, बीमा और आधुनिक तकनीक तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना इसलिए कृषि विकास की अनिवार्य शर्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की भूमिका कृषि विज्ञान को प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुंचाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि वैज्ञानिक प्रगति का लाभ महिला किसानों को मिले। महिला-अनुकूल कृषि उपकरण, श्रम कम करने वाली तकनीकें, कौशल विकास और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। निराई, कटाई, बीज सफाई और प्रसंस्करण जैसे कार्यों में उपयुक्त उपकरण महिलाओं का समय और शारीरिक श्रम बचा सकते हैं। इस परिवर्तन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष महिला वैज्ञानिकों की बढ़ती भूमिका है। कृषि अनुसंधान में महिलाएं अब केवल वैज्ञानिक ज्ञान की उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि नई तकनीकों, पेटेंट और उन्नत पौध किस्मों के विकास में योगदान देने वाली नवाचारकर्ता भी हैं। आईसीएआर के उपलब्ध आंकड़े इस बदलाव की ठोस तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। महिला वैज्ञानिकों ने वर्ष 2021-22 में 31 और 2022-23 में 21 पेटेंट आवेदन दाखिल किए। यह संख्या 2023-24 में 50 और 2024-25 में बढ़कर 71 हो गई। महिला वैज्ञानिकों का योगदान अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक को उपयोगी समाधान में बदलने तक विस्तृत है। पौध किस्मों के विकास और संरक्षण में भी यह योगदान दिखाई देता है। कृषि का भविष्य केवल उत्पादन बढ़ाने में नहीं, बल्कि उपज से अधिक मूल्य सृजित करने में भी निहित है।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

एमपी में मामा बनाम मुख्यमंत्री की जंग तेज!

नीरज कुमार दुबे

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों फिर वही पुराना सवाल सिर उठाने लगा है कि क्या सूबे की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का दखल अब भी उतना ही दमदार है, या मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी अलग लकीर खींचने में जुटे हैं? ऊपर से सब कुछ भाजपा के अनुशासित कुनबे जैसा दिखता है, लेकिन बुधनी के कोसमी गांव से लेकर किसानों की मूंग खरीदी और लाड़ली बहना योजना तक, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने भोपाल के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि ताजा चिंगारी सीहोर जिले के कोसमी गांव से उठी है। यह वही इलाका है, जहां शिवराज सिंह चौहान की बरसों पुरानी राजनीतिक जमीन रही है। गांव में आदिवासी परिवारों के मकान हटाए जाने, फसलों को नुकसान पहुंचाने और कुओं को मिट्टी से भरने की शिकायतों पर शिवराज ने अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। उनका रुख साफ था कि सरकार किसी की भी हो, गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करने की बात कही।

देखा जाये तो राजनीति में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी गांव में मकान टूटे और एक नेता ने नाराजगी जता दी। सवाल यह है कि शिवराज ने यह आवाज उस सरकार के खिलाफ उठाई है, जिसके मुखिया उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव ने भी मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने मुख्य सचिव से जांच कराने और प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास तथा भोजन की व्यवस्था करने की बात कही। दूसरी तरफ, कलेक्टर की रिपोर्ट में वन भूमि पर अतिक्रमण और सागौन के पौधों को नुकसान

पहुंचाने के आरोप सामने आए। यानी मामला केवल सियासी बयानबाजी का नहीं, बल्कि वन संरक्षण, प्रशासनिक कार्रवाई और आदिवासी परिवारों के अधिकारों का भी है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हर घटना का एक स्थानीय और एक राजनीतिक अर्थ होता है। कोसमी का मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि शिवराज ने जिस



इलाके में लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई, वहीं की घटना पर उनका इस तरह सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल अपने पुराने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही है, या इसके पीछे भोपाल की सत्ता के साथ तालमेल का कोई बड़ा सवाल भी छिपा है? इस कहानी का दूसरा सिरा लाड़ली बहना योजना से भी जुड़ा है। शिवराज की राजनीति की पहचान बनी इस योजना ने प्रदेश में महिलाओं के बीच उनकी अलग छवि बनाई।

अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से योजना के खर्च को भारी बताने वाली टिप्पणी ने पुरानी राजनीतिक विरासत और मौजूदा सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ दी है। शिवराज के लिए यह योजना महज सरकारी खर्च का हिसाब नहीं, उनकी राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा है। वहीं, मौजूदा सरकार के सामने बजट, दूसरी योजनाओं और विकास कार्यों के बीच संतुलन बैठाने की चुनौती है।

तीसरा मोर्चा किसानों का है। मूंग की खरीदी को लेकर जब किसान परेशान हुए, तब केंद्रीय कृषि मंत्री

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खरीद तेज करने की मांग की। राज्य सरकार को आखिरकार खरीदी बढ़ाने की मांग पर सहमति देनी पड़ी। देखा जाये तो यहां भी तस्वीर दिलचस्प है। केंद्र में मंत्री शिवराज, राज्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीच में किसान, जिनकी फसल और भुगतान का सवाल सीधे

सरकार की जवाबदेही से जुड़ा है। शिवराज का हस्तक्षेप किसानों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह राज्य सरकार पर दबाव भी बनाता है।

यही वजह है कि शिवराज बनाम मोहन की चर्चा बार-बार लौट आती है। एक तरफ शिवराज हैं, जिनकी पहचान लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के गांव-गांव में बने पुराने संपर्कों से जुड़ी है। दूसरी तरफ मोहन यादव हैं, जिन्हें अपनी सरकार की नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और नेतृत्व की अलग पहचान स्थापित करनी है। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, मगर प्रदेश की राजनीति में उनका असर एक-दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी, हर मतभेद को मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई मान लेना जल्दबाजी होगी। भाजपा में संगठन का अपना अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है। अभी तक सामने आई घटनाएं प्रशासन, किसान नीति और राजनीतिक विरासत पर मतभेद दिखाती हैं; मगर वे किसी औपचारिक सत्ता-संघर्ष को साबित नहीं करतीं।

ललित गर्ग

पंजाब की धरती कभी शौर्य, पराक्रम, मेहनत, उद्यमशीलता और जीवटता के लिए जानी जाती थी। इसी मिट्टी के नौजवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और खेतों में पसीना बहाकर देश का अन्न भंडार भरा। लेकिन आज उसी पंजाब की पहचान नशे के बढ़ते कारोबार, युवाओं की बर्बादी और ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव से जुड़ती जा रही है। यह केवल एक राज्य की सामाजिक त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन-व्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति की गंभीर परीक्षा है। जिस पंजाब के युवाओं के हाथों में कभी तलवार, हल और तिरंगा शोभा देते थे, वहां आज नशे ने अनेक हाथों को बेबस और अनेक परिवारों को बदहवास कर दिया है। विडंबना देखिए कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों की है, यदि उन्हीं के घर से करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामद होने की खबर सामने आती है, तो यह व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने का मामला इसी सड़ांध की ओर संकेत करता है। यह घटना महज एक आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसमें अपराध रोकने के लिए नियुक्त व्यक्ति ही कथित तौर पर अपराध के संदेह के घेरे में आ जाए। यह तो वही स्थिति हुई कि 'बाढ़ ही खेत को खाने लगे', तो फसल की रखवाली कौन करेगा? जिस पुलिस के कंधों पर नशा तस्करों को पकड़ने का दायित्व है, यदि उसी व्यवस्था के भीतर ऐसे तत्व पनपने लगे, तो आम नागरिक का भरोसा डगमगाना स्वाभाविक है। इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। किसी व्यक्ति को केवल

पंजाब में नशे का तांडव : वर्दी बनी त्रासदी



आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। पंजाब में नशे का कारोबार अब गलियों, गांवों और कस्बों तक अपनी जड़ें फैला चुका है। कभी नशे की समस्या को सीमावर्ती क्षेत्रों या शहरी युवाओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज सिंथेटिक ड्रग्स सहित विभिन्न मादक पदार्थों की उपलब्धता ने संकट को और व्यापक बना दिया है। युवा पीढ़ी का एक हिस्सा नशे की गिरफ्त में आकर अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भविष्य गंवा रहा है। कहीं मां की गोद सूनी हो रही है, कहीं वृद्ध पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन रहा है और कहीं परिवार का कमाऊ सदस्य नशे की लत के कारण स्वयं अपने परिवारों पर बोझ बन रहा है। 'घर का चिराग ही घर में अंधेरा कर दे', इससे बड़ी विडंबना क्या होगी! नशे की लत केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक ताने-बाने को भीतर तक खोखला कर देती है। इस संकट की गंभीरता सरकारी आंकड़ों और पुलिस की कार्रवाइयों से भी समझी जा सकती है। उपलब्ध

विवरणों के अनुसार दस महीनों में पंजाब पुलिस ने 10,524 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें 153 बड़े ऑपरेटर शामिल थे। इस दौरान 790 किलोग्राम हेरोइन, 860 किलोग्राम अफीम और अन्य मादक पदार्थों के साथ 13 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी जब्त की गई तथा नशे के कारोबार से जुड़ी 208 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ये आंकड़े कार्रवाई के पैमाने को अवश्य दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ आखिर राज्य में पहुंच कैसे रहे हैं? इतनी गिरफ्तारियों और जब्त के बावजूद यदि नशे की उपलब्धता और लत पर निर्णायक अंकुश नहीं लग रहा, तो स्पष्ट है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। 'मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की' जैसी स्थिति से बचने के लिए गिरफ्तारियों की संख्या से आगे बढ़कर नशे की आपूर्ति, वित्तीय नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की पड़ताल करनी होगी।

पाकिस्तान से लगी पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर लंबी सीमा इस चुनौती को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों

की तस्करी की आशंकाएं सीमा प्रबंधन को और जटिल बनाती हैं। वर्ष 2026 में अब तक पंजाब की सीमा से 183 ड्रोन जब्त किए जाने का उल्लेख इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। सीमा पार से संचालित तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करना आवश्यक है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बाहरी ताकतों पर डालकर राज्य के भीतर की कमजोरियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। यदि स्थानीय तस्कर, संगठित गिरोह और भ्रष्ट तंत्र मिलकर काम कर रहे हों, तो सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ-साथ भीतर भी कठोर कार्रवाई करनी होगी। 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने वाली जांच ही बता सकती है कि इस काले कारोबार में कौन मोहरा है, कौन खिलाड़ी और कौन पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने नशामुक्ति और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अनेक दावे किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे जमीन पर उतना परिवर्तन ला पाए हैं, जिसकी अपेक्षा पंजाब की जनता ने की थी? सत्ता में आने से पहले नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के वादे करना आसान है, लेकिन उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाना राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और निरंतर जवाबदेही मांगता है। यदि नशे की उपलब्धता बनी हुई है, युवा लगातार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और तस्करी के नेटवर्क बार-बार सक्रिय हो जाते हैं, तो सरकार की रणनीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। केवल छापेमारी, गिरफ्तारी और घोषणाओं से नशामुक्त पंजाब का सपना साकार नहीं होगा। सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि नशे की आपूर्ति कितनी घटी, कितने युवा उपचार के बाद सामान्य जीवन में लौटे और बड़े तस्करों तथा उनके संरक्षकों के विरुद्ध कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई।

खान-पान पर दें विशेष ध्यान

सर्दियों में बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन देना बहुत जरूरी है। मौसम बदलने पर कई बच्चे कम पानी पीते हैं। माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा दिनभर पर्याप्त तरल पदार्थ ले रहा है। बच्चे के भोजन में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध या अन्य उपयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। भोजन बच्चे की उम्र और सामान्य आहार के अनुसार होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मौसम ठंडा है, बच्चे को अत्यधिक तला-भुना या बहुत मसालेदार खाना खिलाना जरूरी नहीं है। सर्दियों में बाजार में मिलने वाले बहुत अधिक मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों की जगह घर का संतुलित भोजन बेहतर विकल्प है।

सिर, कान, हाथ और पैरों को ढककर रखें

सर्दियों में बच्चे के शरीर के खुले हिस्सों को ठंडी हवा से बचाना जरूरी है। विशेष रूप से सुबह और रात के समय सिर तथा कानों को ढकना उपयोगी हो सकता है। बाहर जाते समय बच्चे को गर्म मोजे और मौसम के अनुरूप जूते पहनाएं। यदि जूते या मोजे गीले हो जाएं तो उन्हें तुरंत बदल दें। गीले कपड़ों में लंबे समय तक रहने से शरीर ठंडा हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को हर समय सिर से पैर तक अत्यधिक गर्म कपड़ों में लपेटकर रखा जाए। बच्चे को जरूरत से ज्यादा गर्म रखने से भी परेशानी हो सकती है। कपड़े मौसम और बच्चे की गतिविधि के अनुसार होने चाहिए। क्योंकि नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के मामले में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है।

माता-पिता खुद भी रखें ध्यान

बच्चों की देखभाल करने वाले माता-पिता अगर खुद बीमार या अत्यधिक थके हुए हों तो बच्चों की देखभाल प्रभावित हो सकती है। इसलिए माता-पिता को भी अपनी नींद, भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को सर्दियों की मूल सावधानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

सर्दियों में खेलना बंद न कराएं

कई माता-पिता ठंड के डर से बच्चों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। लेकिन सुरक्षित परिस्थितियों में बच्चों का शारीरिक रूप से सक्रिय रहना जरूरी है। मौसम ठीक हो तो दिन के अपेक्षाकृत गर्म समय में बच्चे को खेलने दिया जा सकता है। यदि बाहर बहुत ज्यादा ठंड, कोहरा, बारिश या तेज हवा हो तो घर के अंदर खेलने या शारीरिक गतिविधि के विकल्प तलाश जा सकते हैं। खेलने के दौरान बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से भी बचें। अगर बच्चा दौड़ रहा है और उसे पसीना आ रहा है तो जरूरत के अनुसार कपड़ों की परत कम की जा सकती है। गर्मी की तुलना में सर्दियों में प्यास कम महसूस हो सकती है। इसके बावजूद शरीर को पानी की आवश्यकता बनी रहती है। माता-पिता को छोटे बच्चों को समय-समय पर पानी देने की आदत बनाए रखनी चाहिए। यदि बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी पानी की बोतल साथ भेजें।

बच्चों

का सर्दियां

आने से पहले रखें खास ख्याल

मौसम में बदलाव का असर सबसे पहले छोटे बच्चों पर दिखाई देता है। गर्मी और बारिश के बाद जैसे ही तापमान गिरना शुरू होता है, सुबह-शाम की ठंड बढ़ती है और वातावरण में नमी तथा प्रदूषण का स्तर बदलता है, वैसे ही बच्चों में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार और सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। छोटे बच्चे अपनी परेशानी को हमेशा ठीक से बता नहीं पाते, इसलिए ठंड का मौसम शुरू होने से पहले ही माता-पिता को उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर तैयार रहना चाहिए। ठंड से बचाव का मतलब केवल बच्चों को गर्म कपड़े पहनाना नहीं है। उनके खान-पान, नींद, कमरे के तापमान, साफ-सफाई, स्कूल जाने की दिग्वर्षा, खेलने के समय और संक्रमण से बचाव तक हर पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए सर्दियां शुरू होने से पहले माता-पिता को बच्चों की जरूरत के अनुसार गर्म कपड़े, बिस्तर, जूते-मोजे और जरूरी स्वास्थ्य सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए।

सर्दी-जुकाम को हल्के में न लें

सर्दियों में बच्चों में सर्दी-जुकाम और खांसी आम हो सकती है, लेकिन हर बीमारी को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। यदि तेज या लगातार बुखार है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, बच्चा बहुत सुस्त है, पानी या दूध नहीं ले पा रहा है, लगातार उल्टी हो रही है, स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है तो डॉ. की सलाह लेना जरूरी है।



हंसना मना है

परसों घरवाली ने कहा - मुझे 2,000 रुपये दे दो वापस कर दूंगी...! मैंने पर्स निकाला और पैसे देने लगा तो बोली - अच्छा चलो 1,000 दे दो केवल, 1,000 बाद में ले लुंगी...! आज सुबह बोली - मुझे तुमसे 1,000 लेने हैं.... मैंने पर्स निकाला और 1,000 देने लगा तो फिर बोली - रहने दो मुझे आपको 1,000 देने भी तो हैं, चलो बराबर हो गए...!

पप्पू - जो डर गया, वो मर गया कहावत कैसे बनी? पप्पू - मुझे नहीं पता। तू बता। पप्पू - जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस तभी से ये कहावत बन गई कि जो डर गया, वो मर गया!!!

पति पत्नी से- शादी से पहले तुम बहुत उपवास रखती थी अब क्या हो गया... पत्नी पति से बोली- बहुत नहीं, सिर्फ 16 सोमवार रखती थी... पति- फिर अब क्या हुआ... पत्नी- फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा उपवास से भरोसा ही उठ गया...

कहानी

अंधेरे का भूत

सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही, गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिनभर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डरता कि वो रातभर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधू को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधू को उस पेड़ के पास ले जाते हैं, जहां भूत का वास होता है। साधू अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधू भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधू की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वही, गांव वाले भी उसके पीछे-पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधू भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। कहानी से सीख- समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे राहत मिल सकता है।

7 अंतर खोजें



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष 	कार्यक्षेत्र में नए विचार और नीतियां सफलता दिलाएंगी। व्यापार में नए सौदे तय होंगे। मित्रों और प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।	तुला 	नई नौकरी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं। साझेदारों के साथ मिलकर किए गए काम में फायदा होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा।
वृषभ 	कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। व्यापारिक निर्णय लाभदायक सिद्ध होंगे, प्रगति होगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा।	वृश्चिक 	कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी। व्यापार में नए प्रयोगों से मुनाफा मिलेगा। परिवार में धार्मिक या शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।
मिथुन 	दफ्तर में आपके सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुराने संपर्क व्यापार में नया लाभ दिला सकते हैं। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा।	धनु 	रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। व्यापारिक यात्रा से बड़ा फायदा मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा।
कर्क 	जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसे आप कुशलता से संभालेंगे। व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। परिजनों का पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा।	मकर 	दफ्तर में शांति और एकाग्रता से काम लें। व्यापार में कागजी काम ध्यानपूर्वक पूरे करें। पारिवारिक मामलों में बड़ों की सलाह लें। बजट के अनुसार खर्च करना समझदारी होगी।
सिंह 	सहकर्मियों का सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे। व्यावसायिक सौदों में लाभ की संभावना अच्छी है। दायित्व जीवन में सुख और मिठास बनी रहेगी।	कुम्भ 	आपकी कार्यकुशलता से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। नए अनुबंध या सौदों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, संबंध प्रगाढ़ होंगे। शनि स्त्रोत का पाठ करें।
कन्या 	कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें। लेन-देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। अपनों से बातचीत में संयम बनाए रखें। खान-पान में संतुलन रखें।	मीन 	कार्यस्थल पर आपके विचारों का स्वागत होगा। व्यापार में नए ग्राहकों का साथ मिलेगा। परिवार में सौहार्द और खुशहाली का माहौल रहेगा।

का र्तिक आर्यन और श्रीलीला की आने वाली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म, जिसका निर्देशन अनुराग बसु कर रहे हैं, अब 30 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। पहले इस फिल्म को दिसंबर 2025 में रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह अगले साल सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म के मेकर्स ने 15 अक्टूबर को नई रिलीज डेट की घोषणा की, हालांकि उन्होंने अभी भी फिल्म का टाइटल गुप्त



कार्तिक-श्रीलीला की फिल्म 30 अप्रैल को होगी रिलीज

रखा है। सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कार्तिक और श्रीलीला की एक तस्वीर शेर कर रहे हुए मेकर्स ने रिलीज डेट की जानकारी दी। यह वही तस्वीर है जिसका इस्तेमाल पहले इस प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए किया गया था। पोस्ट में लिखा गया, एक नई कहानी जो आपके दिल में बस जाएगी, अब बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन और श्री लीला

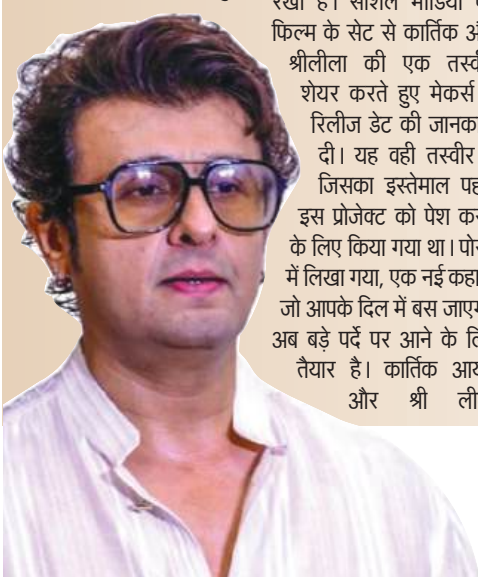
स्टार, अनुराग बसु द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार के प्रोडक्शन में बनी अनटाइटल्ड फिल्म 30 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में आएगी। इस घोषणा के बाद फैंस के रिएक्शन आए, जिनमें से कई ने रिलीज डेट मिलने पर राहत जताई। कुछ फैंस ने मेकर्स से फिल्म का टाइटल बताने की भी अपील की। इस फिल्म में पहली बार कार्तिक और श्रीलीला एक साथ काम कर रहे हैं, और अनुराग बसु इस रोमांटिक म्यूजिकल

फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। भूषण कुमार की टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म में संगीत प्रीतम ने दिया है। नई रिलीज डेट तब सामने आई है जब फिल्म के पुराने शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया था, जिससे इसके प्रोडक्शन टाइमलाइन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अनुराग बसु ने पहले कहा था कि शूटिंग योजना के अनुसार चल रही है और पूरी टीम फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

जेन-जी संयम भूल जाएंगे तो खुद को नंगा साबित करेंगे : इला अरुण

अपनी बुलंद आवाज से देश-दुनिया में कला का परचम लहराने वाली फेमस एक्ट्रेस और राजस्थानी फोक सिंगर इला अरुण गुरुवार को आजतक पंचायत राजस्थान के मंच पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर और अपने चिर-परिचित अंदाज में बात की। आज की युवा पीढ़ी (जेन-जी) और उनके घरने-प्रदर्शन के तरीकों पर बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि भाषा व्यक्ति का वस्त्र होती है, और अगर आप संयम भूल जाएंगे तो छिछोरी भाषा कहेंगे तो आप खुद को ही नंगा साबित करेंगे। प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करने वालों से वह बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी,

खासकर लड़कियों को होश खोते देखा, तो उन्हें बहुत शर्म आई। उन्होंने कहा कि संस्कृति को भूलना और इस तरह का बर्ताव करना सरकार की नहीं बल्कि मां-बाप और खुद युवाओं की जिम्मेदारी है। आजकल के बिगड़े हुए रैप सॉन्स के लिए भी उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं की सोच को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान और बाहर परफॉर्म करने के अंतर पर बात करते हुए उन्होंने दिल की बात खुलकर रखी। इला ने कहा कि उन्होंने यहां ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि बात दूर तक निकल जाएगी। उनके गानों पर आज भी तीन-तीन पीढ़ियां झूम रही हैं और उन्होंने राजस्थान को विश्व पटल पर पहुंचाया है। विवादित गानों के दौर और आज के गानों की तुलना पर इला अरुण ने साफ किया कि चोली के पीछे क्या है कोई बल्गर गाना नहीं था। सुभाष घई खलनायक फिल्म के 50 साल मना रहे हैं, और उस गाने में लड़के का सवाल था तो लड़की ने भी जवाब में यही कहा था कि चोली के पीछे दिल है मेरा।



सोनू निगम के द रेवोल्यूशन इंडिया टूर पर विवाद

कैसिल हो सकता है बेंगलुरु कॉन्सर्ट

महशूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम के फैंस को गहरा झटका लगा है। इसी महीने 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला उनका द रेवोल्यूशन इंडिया टूर विवादों में घिर गया है। बहुत संभव है कि इस टूर का पहला कॉन्सर्ट ही कैसिल करना पड़े। 53 साल के सोनू निगम इस टूर की शुरुआत बेंगलुरु से करने वाले हैं, लेकिन इस शो पर अप्रैल 2025 का कन्नड़ भाषा विवाद हावी होता दिख रहा है। सिंगर ने बीते साल बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में शो के दौरान कथित विवादित टिप्पणी की थी। अब कर्नाटक रक्षण वेदिके नाम के संगठन ने सिंगर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतावनी दी है कि अगर सोनू निगम का कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, तो विरोध की चिंगारी पूरे कर्नाटक में फैल सकती है। मामले को गंभीर बताते हुए संगठन ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से कॉन्सर्ट की अनुमति न देने और यदि अनुमति पहले ही मिल चुकी है, तो उसे रद्द करने की मांग की है। केआरवी का आरोप है कि सोनू निगम की कथित टिप्पणी ने कन्नड़ भाषा के प्रति लोगों के प्रेम, गर्व और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। संगठन ने साफ शब्दों में कहा, कन्नड़ लोगों ने इस जख्म को अभी तक नहीं भुलाया है। केआरवी के प्रदेश अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को पत्र सौंपकर कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि सोनू निगम ने कन्नड़ भाषा के प्रति लोगों के प्रेम की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से करके कन्नड़ समुदाय का अपमान किया था। पत्र में सवाल उठाया गया है, क्या कन्नड़ गाना मांगना कोई अपराध है? सोनू निगम को यह अधिकार किसने दिया कि वे कन्नड़ भाषा के प्रति प्रेम की तुलना किसी आतंकी हमले से करें?

दीपिका के समर्थन में उतरीं इशिता दत्ता

पि छले दिनों जब दीपिका पादुकोण फिल्म स्पिरिट से अलग हुई, तो ऐसी खबरें आई कि यह फैसला उनकी तरफ से 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करने की वजह से लिया गया था। तब से बॉलीवुड में काम के लंबे घंटों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में दृश्यम 3 की अभिनेत्री इशिता दत्ता ने दीपिका की मांग का समर्थन किया। इशिता ने कहा, आठ घंटे की शिफ्ट देना या न देना आपकी निजी पसंद है, इसलिए प्रोडक्शन हाउस मना कर सकता है।

मगर इसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाना और इसे गलत ठहराने की कोशिश करना गलत है। ऐसे कई कलाकार हैं जो 12-15 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति की मांग को अनुचित बताकर उसे कमतर नहीं आंक सकते। अभिनेत्री ने आगे कहा, जब आप खुद एक बच्चे की मां बनती हैं, तब आपको समझ आता है कि इसमें कितनी

मेहनत और समय लगता है। अगर मेरे पास भी ऐसी स्थिति होती जहां मैं मांग रख सकती, तो शायद मैं भी मांगती। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस मुकाम पर हूं। इससे पहले दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में काम के माहौल और वेतन में समानता को लेकर चल रही बहस पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, मैंने कई

दृश्यम 3 की अभिनेत्री बोलीं- आठ घंटे की शिफ्ट देना या न देना आपकी निजी पसंद है

स्तरों पर ऐसा किया है। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जहां तक वेतन की बात है, मुझे

इससे जुड़ी हर स्थिति का सामना करना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि इसे क्या नाम दूं, मगर मैं हमेशा अपनी लड़ाइयां चुपचाप लड़ती आई हूं। पता नहीं क्यों, कभी-कभी ये बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, जो मेरे तरीके से अलग हैं और मेरी परवरिश भी ऐसी नहीं रही है। बता दें कि दो अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर

अच्छा कलेक्शन किया है। 12 दिनों में इसने दुनियाभर में 501 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी।



राजपाल को पासपोर्ट मिलेगा वापस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैसे कमाएं, कर्ज चुकाएं

चे क बाउंस केंस में फंसे राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राजपाल का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। ताकि वो शूटिंग के लिए कनाडा जा सकें और काम कर उधार की रकम चुका सकें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राजपाल से कहा- जाइए, पैसे कमाइए और कर्ज चुकाइए। सुप्रीम कोर्ट एक मीडिएटर (मध्यस्थ) भी अपॉइंट करेगा, जो कि राजपाल यादव और उनके लेनदारों के बीच वित्तीय विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। यकीनन राजपाल के लिए ये खुशी की बात है। उनके विदेश

ट्रैवल करने में आई अड़चन अब सुलझ गई है। वहीं सीजेआई की टिप्पणी ने साफ कर दिया कि कोर्ट चाहता है कि राजपाल यादव काम करें और अपने वित्तीय मैटर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने के बाद राजपाल कर्ज चुकाने को लेकर किसी भी तरह का एक्ज्यूज नहीं बना पाएंगे। इससे पहले 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव पेश हुए थे। सीजेआई ने राजपाल से कहा था कि आप कुछ अच्छी फिल्में बनाओ, लोगों को एंटरटेन करो। जज के सामने राजपाल का दर्द छलका था। एक्टर ने कोर्ट में कहा कि लोगों का

मनोरंजन करते हुए मैं खुद ड्रामा बन गया हूं। मेरा बहुत सारा पैसा डूब गया है। इस फिल्म में मुझे 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पिछले 13

सालों से इन लोगों ने मेरी फिल्म नहीं बनने दी। उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया था। उन्होंने बदले की नीयत से अपने 5 करोड़ रुपये के चक्कर में मेरा 22 करोड़ रुपये का नुकसान करवा दिया। शुरुआत में मुझसे कहा था कि मैं 100 करोड़ रुपये का आदमी हूं। फिर धमकाया कि वो मुझे अदालतों में घसीटेगा। ?मैं सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा हूं। अब मैं खुद एक ड्रामा बन गया हूं। ?मैंने 200 फिल्मों की

हैं और उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मुझे फिर से काम मिलने लगा है। मैं उनका पैसा चुका दूंगा। राजपाल ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्जा लिया था। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। एक्टर को चेक बाउंस मामले में जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अभी तक राजपाल इस केंस से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

अब शूटिंग के लिए जा पाएंगे कनाडा

महिला अधिकारी से गलत बर्ताव पर जम्मू-कश्मीर में सियासी तनाव

» कुमार राजीव रंजन को प्रदेश से निष्कासित किया जाए : फारूक अब्दुल्ला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक महिला अधिकारी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आईएसए अधिकारी कुमार राजीव रंजन को जम्मू-कश्मीर से निष्कासित करने की मांग करते हुए कहा कि उनके व्यवहार में शालीनता नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके कार्यकाल में, जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य था, ऐसी घटना हुई होती तो वह उस अधिकारी को वापस विमान में बिठाकर रवाना कर देते। अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह पूरी तरह गलत थी। उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि उनमें वह शालीनता और मर्यादा नहीं है, जो एक अधिकारी में होनी चाहिए। अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे लोगों की बात सुनें।

मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं सीएम : महबूबा

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी कुमार राजीव रंजन का एक महिला अधिकारी के साथ 'अपमानजनक' व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता

और मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। महबूबा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, इस तरह का अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री उमर

अब्दुल्ला को तत्काल यह मामला भारत सरकार के समक्ष उठाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, जिस पर पहले से ही अवैध बंदूक लाइसेंस जारी करने के आरोप है।

सरकार ने दिये जांच के आदेश

जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुमार राजीव रंजन द्वारा कथित दुर्यवहार की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 2004 बैच की आईएसए अधिकारी और आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त-सचिव मंदीप कौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक कर्ी ने एक पत्र में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यह भी आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी बीनिश वानी को किसी भी तरह से 'प्रताड़ित' न किया जाए और न ही उनके खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई की जाए। इस मामले में उपराज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की जरूरत है। पता लगाए कि क्या सेवा नियमों या अपराध के मानकों का उल्लंघन हुआ है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के पद की परवाह किए बिना उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

होने का तो सवाल ही नहीं उठता। श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव इस सप्ताह की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका को लेकर गांदरबल की सहायक निदेशक (रोजगार) बीनिश वानी के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद विवादों में घिर गए।

नामांकन में बाधा डाल रही टीडीपी: लेल्ला अप्पी

» वाईएसआरसीपी ने मांगी सुरक्षा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक पत्र में, वाईएसआरसीपी राज्य महासचिव और लेल्ला अप्पी रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकर्ताओं ने वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों से जबरन नामांकन पत्र छीन लिए, जिससे वे अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सके। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप करके उम्मीदवारों की सुरक्षा नहीं की, जबकि कई मामलों में कार्यकारी अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों ने वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया है कि कडप्पा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके उम्मीदवारों को डराया-धमकाया जा रहा है और उनके काम में बाधा डाली जा रही है।

पंजाब में झोटा की हत्या पर राजनीतिक घमासान

» नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह के परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार

» राजनीतिक दलों ने आप सरकार को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की मानसा में हुई सनसनीखेज हत्या के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस घटना के तीन दिन बीत जाने के बावजूद परिवार ने न्याय मिलने तक अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया है, और झोटा का शव अभी भी सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। इस संवेदनशील मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झोटा की हत्या की गहन जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि जांच के दौरान किसी भी साजिश का पता चलने पर उसका पर्दाफाश किया जाएगा।



वहीं, झोटा के परिवार ने न्याय मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। मानसा में झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने के तीन दिन बाद भी उनका शव सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार झोटा की हत्या और पिछले महीने गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगेगी। गुलजार सिंह ने अपने इलाके में नशीले पदार्थों की आपूर्ति

गलत काम करने वाले को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा : मान

इस घटना के बाद पंजाब में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मान ने 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के तहत समीक्षा बैठक के लिए फिल्लौर में कहा, "गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, घटना से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और जांच के दौरान किसी भी साजिश का पता चलने पर उसका पर्दाफाश किया जाएगा।" मान ने समाज के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के संकल्प को ऐसी घटनाओं से कमजोर न होने देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके पीछे की सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस हाई-प्रोफाइल हत्या मामले ने राजनीतिक दलों को सतारूढ़ सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से जारी है।

को लेकर एक मंत्री से सवाल किया था।



पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन कथित घटनाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा बताते हुए, अप्पी रेड्डी ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह संबंधित चुनाव और पुलिस अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी करे। इन निर्देशों का उद्देश्य उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकना और तय नियमों के अनुसार नामांकन पत्र स्वीकार करना है। पत्र में आयोग से यह भी कहा गया है कि वह अनुपालन रिपोर्ट मंगाए।

न्यूजीलैंड दूर के लिए भारत की टेस्ट व वनडे टीम घोषित

» शमी को नहीं मिला मौका, आकाशदीप की वापसी, पंत की फिटनेस पर नजर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं, तेज गेंदबाज आकाश दीप की एक साल से अधिक समय बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी। टीम में पंत के साथ ध्रुव जुरेल को भी

विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। ऐसे में पंत की फिटनेस और मैच खेलने की स्थिति पर चयनकर्ताओं तथा टीम प्रबंधन की नजर रहेगी। टीम में मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं है। उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह नहीं दी। दूसरी ओर, आकाश दीप की वापसी भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए अहम मानी जा रही है। वहीं वनडे सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों में शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर



को अंतिम दो मैचों के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, ईशान किशन को चौथे और पांचवें वनडे के लिए उपकप्तान बनाया गया है। टेस्ट और वनडे सीरीज के बीच कम समय को ध्यान में रखते हुए चयनकर्ताओं ने टीम में यह बदलाव किया है। शुभमन गिल शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों में 16 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। केएल राहुल के अलावा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा केवल शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम का हिस्सा होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा की उपलब्धता उनकी फिटनेस और बाई हेमस्ट्रिंग की चोट से उबरने पर निर्भर करेगी। वनडे टीम में मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर

नीतीश की खातिर की नौ हत्याएं: अनंत

» जदयू ने आरोपों को नकारा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने अतीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद के लिए नौ लोगों की हत्या करवाई थी। आगामी विधान परिषद चुनाव में नीरज कुमार को टिकट मिलने से नाराज सिंह ने जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही है। वहीं जदयू ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पांच दशक का राजनीतिक जीवन पूरी तरह बेदाग रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से नाराज बताये जा रहे विधायक अनंत कुमार सिंह ने दावा किया कि उन्होंने नीतीश कुमार की मदद के लिए नौ लोगों की हत्या करवाई थी।



आगामी विधान परिषद चुनाव में जदयू द्वारा नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने से मोकामा से विधायक सिंह नाराज हैं। नीरज कुमार, विधान परिषद के तीन बार सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने नीरज कुमार को हराने का संकल्प लेते हुए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करने की बात भी कही है। अनंत सिंह ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा, "नीतीश कुमार और मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। उनकी मदद करने के लिए मैंने नौ लोगों की हत्या करवाई। जब वह संघर्ष कर रहे थे और राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं उनके साथ खड़ा था।" सिंह ने कहा कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करना नीतीश कुमार की अवहेलना नहीं है। उन्होंने 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसी वर्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। विवादित बयानों के लिए चर्चित सिंह ने कुछ घंटे बाद सफाई देने के लिए पत्रकारों को अपने आवास पर बुलाया हालांकि, इस दौरान उनके बयान से जदयू की मुश्किलें बढ़ गईं। इस बीच, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक वीडियो बयान जारी कर पार्टी को इस विवाद से अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने अनंत सिंह का नाम लिए बिना कहा कि नीतीश कुमार का 50 साल का राजनीतिक करियर बेदाग रहा है।

स्मृति मंथाना के कप्तानी युग का जीत से आगाज

रायपुर। भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। रायपुर में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए जिम्बाब्वे को चार विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 114 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने निकी प्रसाद और दीपति शर्मा की शानदार पारियों के दम पर 15.4 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य लक्षित कर लिया। इस मुकाबले के साथ ही स्मृति मंथाना के भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के नए दौर की शुरुआत भी जीत के साथ हुई। 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 19 रन के स्कोर पर अपने चार अहम विकेट गंवा दिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा उल्टफेर कर सकती है, लेकिन इसके बाद निकी प्रसाद और दीपति शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली।

कुमार को जगह नहीं मिली है।

योगी जी! आयुष्मान कार्ड दिखाएं या फिर ऊपर से सोर्स लगाएं

40

हजार रुपये से ज्यादा का खर्च हो गया 10 घंटे में

स्पेशल डॉक्टर के नहीं पहुंचने और आयुष्मान पर इलाज से इनकार

- लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में गंभीर मरीज के इलाज को लेकर परिजनों की शिकायत
- फोन पर मिला सिफारिश का रास्ता तलाशने की सलाह
- डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जवाबदेही के सवाल



क्या आयुष्मान मरीजों को नहीं देखते विशेषज्ञ डॉक्टर?

फोन पर बातचीत के दौरान संबंधित व्यक्ति ने यह भी कहा कि डॉ. आमिर आयुष्मान योजना के मरीजों को नहीं देखते। सवाल बढ़ा हो गया है कि क्या स्पेशल डाक्टर आयुष्मान कार्ड मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।



नहीं मिलने की शिकायत की दर्ज करायी है। अस्पताल में फोन कर जानकारी लेने पर भी ऐसा

हेल्थ मिनिस्टर सर इस शिकायत पर भी तत्परता दिखाइये

उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अस्पतालों के निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को लेकर सक्रियता दिखाते रहे हैं। ऐसे में इस शिकायत पर भी तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव और मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से अपेक्षा है कि वे अस्पताल प्रबंधन से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगें। मरीज को किस समय किस डॉक्टर ने देखा? फेफड़ों के विशेषज्ञ को बुलाने में देरी

क्यों हुई? शुरुआती दस घंटों में लिए गए करीब 40 हजार रुपये किन सेवाओं, जांचों, दवाओं या अन्य मदों के लिए थे? क्या मरीज आयुष्मान योजना के तहत पात्र था? संबंधित अस्पताल में उस उपचार की सुविधा और योजना की स्वीकृति उपलब्ध थी या नहीं? यदि उपचार से इनकार किया गया तो उसका नियमसम्मत कारण क्या था? इन प्रश्नों के जवाब दस्तावेजों के आधार पर सामने आने चाहिए।



लखनऊ। सरकार कहती है कि गरीब के पास आयुष्मान कार्ड है तो पांच लाख रुपये तक के उपचार का सुरक्षा कवच है। लेकिन जब गंभीर मरीज अस्पताल पहुंचता है और उसके परिवार को यह सुना पड़े कि कार्ड पर इलाज नहीं हो पाएगा कहीं ऊपर से सोर्स लगवा दीजिए तब सवाल केवल एक अस्पताल का नहीं रह जाता। सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे गरीब परिवार बीमारी के सबसे मुश्किल वक्त में सरकारी योजना का दरवाजा खटखटाता है।

मऊ से लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल पहुंचे एक गंभीर मरीज के परिजनों ने इलाज में देरी शुरुआती घंटों में भारी खर्च और आयुष्मान कार्ड के बावजूद उपचार

135 किलो ड्रग्स केस से तमिलनाडु में सियासी तूफान

- टीवीके नेता गिरफ्तार एमके स्टालिन ने सीएम विजय को घेरा

लखनऊ। 4पीएम न्यूज नेटवर्क चेन्नई। मिलनाडु की सत्ताधारी तमिलनाडु वेन्नी कडगम (टीवीके) के एक नेता को नागापट्टिनम में मेथामफेटामाइन नाम के ड्रग्स तस्करी के कथित मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है।

उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि मामले में करीब 135 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत कई सौ करोड़ रुपये बताई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस खेप को श्रीलंका भेजने की योजना थी। हालांकि छत्रछ्त्र ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। टीवीके के प्रवक्ता एम. सत्य कुमार ने कहा कि जैसे ही पार्टी को आरोपों की जानकारी मिली, बूबलन को तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, जैसे ही पार्टी को इसकी जानकारी मिली, संबंधित पदाधिकारी को

टीवीके ने आरोपी को पार्टी से निकाला

गिरफ्तार नेता बूबलन को टीवीके ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी का कहना है कि अवैध गतिविधियों में कथित सलिपता उसके सिद्धांतों और मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बूबलन से किसी भी प्रकार का संबंध न रखें। इस बीच सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय के साथ बूबलन की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।

उदयनिधि ने जांच की मांग की

उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में विजय के चर्चित अभियान संदेश नशा छोड़ो, खेल अपनाओ का जिक्र करते हुए सरकार की नशा विरोधी नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि मादक पदार्थ कहाँ से आए, इन्हें खरीदने वाले कौन हैं और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं? उदयनिधि ने यह भी आरोप लगाया कि तस्करी में प्रभावशाली लोगों को पैसा दिया गया होगा। उन्होंने एनआईए और ईडी से मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।

हटा दिया गया। हम हर सदस्य का बैंकग्रांड चेक नहीं कर सकते। कई बार लोग नेताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं सत्य कुमार ने यह भी कहा कि पहले डीएमके के शासनकाल में जाफर सादिक की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें पार्टी से बाहर किया था।

फार्मा कंपनी में रिक्क्टर फटने से 5 लोगों की मौत

लखनऊ। 4पीएम न्यूज नेटवर्क अहमदाबाद। गुजरात के भरूच जिले के वागरा तालुका के सायखा में स्थित सिंजिल फार्मा कंपनी में एक रिक्क्टर अचानक फट गया। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हुआ ये विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं पांच गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए भरूच के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिक्क्टर में विस्फोट होने से ये हादसा हुआ है।

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से दहला ग्रेटर नोएडा

लखनऊ। 4पीएम न्यूज नेटवर्क नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीपदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतकों में पति, पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला जहर खाने का प्रतीत हो रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की

पहचान महेश (36), उनकी पत्नी ललिता (34), बेटा लड्डू (12), बेटी मिस्टी (8) और सबसे छोटी बेटी साक्षी (4) के रूप में हुई है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

कांग्रेस नहीं जनता चाहती है सत्ता परिवर्तन: सिब्ल

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर राज्यसभा सांसद का पलटवार

लखनऊ। 4पीएम न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्ल ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सिब्ल ने कहा कि जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है और अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। सिब्ल की यह टिप्पणी राजनाथ सिंह के उस बयान के एक दिन बाद

आई है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा था। सिंह ने उन पर आरोप लगाया था कि वे बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि लोकतंत्र किसी को भी अव्यवस्था फैलाने या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने की छूट नहीं देता है। एक्स पर एक पोस्ट में सिब्ल ने कहा, राजनाथ सिंह-आप आरोप लगाते

हैं कि कांग्रेस बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन चाहती है। नहीं। असल में जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। निर्दलीय सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के नारों वाले विरोध-प्रदर्शनों ने ही आपको सत्ता दिलाई थी। लेकिन बाद में आपने भ्रष्टाचार को अपना लिया, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया और मतदाता सूची में हेरफेर की। अब आपके जाने का समय आ गया है! शुक्रवार को सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी, सीधे तौर पर या अपने समर्थक संगठनों के जरिए, युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र-निर्माण में लगाने के बजाय, उसका इस्तेमाल राजनीतिक टकराव बढ़ाने और अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं।